RAJYA SABHA

Thursday, the 20th March, 1997/ 29th Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I have asked for suspension of Question Hour to raise a matter of urgent public importance. This House has been seized of the matter of Almatti Dam in the past few weeks and there is an Expert Committee Report which has shown gross violation by Karnataka of all the norms that we decided on. Sir, this is not something which I am saying as an individual. Sir, they are irrefutable. This Committee was appointed by both the Governments represented by their respective Chief Secretaries, various members of their Governments. They also came and investigated Andhra Pradesh and besides violations of the Bachawat Award, the Experts Committee has also shown that irrevocably there are other violations. Our demand now is that Karnataka must immediately stop the construction of Almatti Dam because the intent is dubious and they have been funded by funding agencies the world over including the World Bank. By misleading the facts...(*Interruptions*)...Sir, we will stop. There is no question of compromise on the issue of the people of Andhra Pradesh. (*Interruptions*)

SHRI S. M. KRISHNA: (Karnataka) Sir, it is a life and death question for Karnataka.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: When an Experts Committee has been appointed, there has to be a sanctity...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am sorry, today...(*Interruptions*)... Please sit down. (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How can he dispute it? Four Chief Ministers have decided on this Report.

MR. CHAIRMAN: Yes, I understand. I understand it. Today we happen to have a lot of urgent Government business to be done. I think if you wish to raise it tomorrow, I will allow you to raise it in the Zero Hour. Thank you.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Question No. 361.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा असम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित किया जाना

*361. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा असम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करने हेतु सरकार ने जो योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम आदि स्वीकृत किये हैं, उनका स्वीकृत धनराशियों सहित ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमों और कार्यक्रमों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक माहौल तैयार करना, सूचना का प्रचार, प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग पैदा करना, परियोजनाओं को अनुमोदन देना, कोल्ड चेन समेत फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना, बैकवर्ड लिंकेज की अवधारणा का तथा ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, अनुसंधान और विकास कार्यों में सहायता करना, राज्य सरकारों से परस्पर संपर्क बनाए रखना तथा हमारी योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। ये कार्यकलाप असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत सारे देश से संबंधित हैं। इन राज्यों को क्रमशः 523.23, 180.20 और 8.21 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 8वीं योजना अवधि के दौरान दी गई है।

श्री शिवचरण सिंह: माननीय सभापति जी.....(**व्यवधान**)..... There should not be any interruptions in the Question hour. (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the Prime Minister has come to the House. May I please draw his attention to the Report of the Experts Committee? (*Interruptions*) What is this? I should be allowed to draw his attention. It is my right. How can you say this? Through you, Sir, I would request the Prime Minister to be here in this House tomorrow at Zero Hour.

MR. CHAIRMAN: The Prime Minister must have seen it already. Please raise it tomorrow. Please put the first supplementary.

श्री शिव चरण सिंह: माननीय सभापति जी, मेरा प्रथम सप्लीमेंटरी यह है कि प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करने हेतु भारत की जो योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम आदि स्वीकृत किए हैं, उनका स्वीकृत धनराशियों सहित ब्यौरा क्या है? इन्होंने कंसॉलिडेटेड फंड दिया है असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश का लेकिन मैंने स्कीमवाइज़ पूछा है। माननीय मंत्री जी, मैं पूरे डीटेल जानना चाहता था कि कौन सी स्कीम को कितना रुपया, किस प्रांत को कितना रुपया दिया है? आपका उत्तर पूर्ण नहीं है नंबर एक। फिर भी मैं प्रश्न करता हूं कि आपने जो मल्टीनेशनल्स को ऐलाऊ किया है राजस्थान में, पिछली बार आपको याद होगा कि एक प्रश्न आया था कि भुजिया, बीकानेरी भुजिया और सेम के बारे में मल्टी नेशनल्स को आपने इनकरेज किया है। महोदय, राजस्थान से माल्टा पैदा होता है और भारी तादाद में यह पैदा होता है जिसके ऐक्सपोर्ट की प्रॉब्लम तब से है जब से अरब कंट्रीज को ऐक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह से साइट्रेट प्लांट है जो एक बहुत अच्छा फ्रूट है। माल्टा, ब्लड रैड माल्टा और नीक कीनू यह तीन फ्रूट्स राजस्थान में भारी तादाद में होते हैं जिनको ऐक्सपोर्ट न होने की वजह से खत्म करना पड़ता है। उनके प्रोसैसिंग के बारे में आपने क्या योजना बनाई है, कितनी स्कीम्स आपके सामने आई हैं और अगर नहीं आयी हैं तो क्यों नहीं बनवायी? किसलिए यह डिपार्टमेंट बना है? जहां जरूरत है, वहां नहीं बनाते। इसी प्रकार से जो जो स्वीकृत राशि है, असम फुल ऑफ फ्रूट्स है, वहां तमाम प्रकार के फ्रूट्स पैदा होते हैं और...

MR. CHAIRMAN: Mr. Singh, please conclude. You please put a question.

श्री शिवचरण सिंह: महोदय, मेरे प्रश्न का तात्पर्य यही है कि यह समझें और उत्तर दें और हमें भी समझाएं। असम को केवल 8.21 लाख रुपया आठवीं योजना के अंत तक दिया है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे: अभी इनको पूछिए कि कितने सवालों के कितने जवाब देने हैं?

श्री शिव चरण सिंह: तो आप कृपया इन सबके उत्तर दें।

श्री दिलीप कुमार राय: महोदय, असम के बारे में वहां अभी तक जो 8.23 करोड़ दिये गये हैं, उसके बाद some big industries are coming up.असम में एनुअल सर्वे आॅफ इंडस्ट्रीज़ की रिपोर्ट के हिसाब से वहां 662 यूनिट हैं और इनवैस्टमेंट 710 करोड़ रुपये हुई है। अभी जो आई॰एम॰ फाइल्ड हुआ है, उसमें 5 आई॰एम॰ फाइल्ड हुआ है जिसका टोटल इनवैस्टमेंट 194 करोड़ रुपये होगा जिसमें 270 लोगों का इम्पलॉयमेंट प्रोटैक्शन है। राजस्थान के बारे में जो इन्होंने कहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को लगाने की जरूरत है। वहां की जो ऐग्रीकल्चर ग्रोथ है, वहां हर स्टेट में नोडल एजेंसी होती है और नोडल एजेंसी जो हर स्टेट में है जैसे राजस्थान में है, डायरैक्टर इंडस्ट्रीज़ है, उनसे पूछकर वह लोग जो रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रोजैक्ट्स को फाइनेंस करते हैं और हैल्प करते हैं।

श्री शिव चरण सिंह: मान्यवर, मैंने पूछा है...**(व्यवधान)**...

श्री शिव चरण सिंह: मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि मल्टी नेशनल्स जो कंज्यूमेबल आर्टीकल्स का लाइसेंस लेकर यहां फैक्ट्रीज डैवलप कर रहे हैं, जैसे अंकल चिप्स आप सब लोग खाते हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी: हम नहीं खाते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री शिव चरण सिंह: आप अंदाजा कीजिए, प्रत्येक माननीय सदस्य को मालूम है कि उनकी कीमत कितनी हो गयी है। क्या उस पर आप पाबंदी लगाएंगे और इंटरनल मार्किट के अंदर लाइसेंस लेने के बाद केवल ऐक्सपोर्ट करेंगे और इंटरनल मार्किट में नहीं बेचेंगे? क्योंकि हिन्दुस्तान में सब चीजों को उनके रैपर से प्रभावित होकर ठगाया जा रहा है और अरबों रुपये की भुजिया, पापड़, अंकल चिप्स और तरह-तरह की लैप जूस की गोलियां, मान्यवर, आपको तो मालूम है, पकड़ाते और खिलाते हैं। उससे हमारी इंटरनल मार्किट भारी रूप से खराब हो रही है, उसको बैन करने के

लिए क्या कोई लैजीस्लेशन या कानून लाएंगे?

श्री दिलीप कुमार राय: सर, यह जो राजस्थान की भुजिया की बात है, पैप्सी को करीब डेढ़ साल भुजिया बिज़िनेस में आए हुए हुआ है। इसमें कोई आथैंटिकेटिड फिगर नहीं है लेकिन भुजिया मार्किट का 80 परसेंट शेयर अभी भी ऑरगेनाइज सैक्टर में हल्दीराम के पास है।

श्री शिव चरण सिंह: हल्दीराम का कोलैबोरेशन पैप्सी से है।

श्री दिलीप कुमार राय: नहीं है सर। मैं बता रहा हूं। Haldiram is the main competitor to Pepsi. 80 परसेंट ऑरगेनाइज़ सैक्टर में हल्दीराम के पास है। क्योंकि स्नैक फूड में पोटैटो चिप्स है, भुजिया है—Indian market is 300 thousand tonnes. 1800 करोड़ रुपये का यह है जिसमें लोकल एंटरप्रेन्योर they have a say in this. आरगेनाइज़ सैक्टर में भी हम लोगों का अच्छा हो रहा है। Even if the multinational companies come, I don't think they will hit the local entrepreneurs. They know the taste and palate of the Indian people better and I don't think there should be any problem.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Parag Chaliha.

श्री शिव चरण सिंह: मान्यवर, प्लांट जो लगाया गया, वह ऐक्सपोर्ट के लिए लगाया गया और केवल इंटरनल मार्किट में वह बेच रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि इंटरनल मार्किट में बेचने पर क्या आप पाबंदी लगाएंगे? आप साफ जवाब दीजिए, पाबंदी लगाएंगे कि नहीं? 4000 करोड़ रुपये विदेशियों ने यहां आकर इनवैस्ट कर दिये और आपने इतने नहीं किये। तो थोड़े दिन में तो वह हमारे घर में जाकर झगड़ा करेंगे, रोटी भी वह बनाएंगे।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): Sir, the Minister is absolutely wrong.

श्री दिलीप कुमार राय: सर, पाबन्दी तो नहीं लगा सकते हैं।

श्री शिव चरण सिंह: क्यों नहीं लगा सकते हैं? हमारी फूड प्रोसेसिंग का मतलब था अचार, रस, मुरब्बे और विदेशों में उपयोग में आने वाली चीजें, एक्वाकल्चर के माध्यम से फिश, टिड फिश या हमारा ऐग पाउडर। अब हमारी रोटी, भुजिया, दाल इसमें भी अगर आपने फॉरेनर्स को घुसा दिया है तो क्या हिन्दुस्तान की डाइटिंग पेटर्न, हिन्दुस्तान की संस्कृति सबको आप सप्रेस करना चाहते हैं?

SHRI DILIP KUMAR RAY: Sir, we will take steps to protect our Indian industry also. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Shri Parag Chaliha. *(Interruptions)* I have called Mr. Parag Chaliha. (*Interruptions*) Please. I have called him.

SHRI PARAG CHALIHA: Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. In reply to a question on 11.7.1996, a list about industrial enterpreneurship, memoranda implementation, was given. It makes a shocking reading so far as development of this particular industry in Assam and the North-East is concerned. I will read it out. The list gives the State-wise summary of items. In Assam the number of items is zero. Proposed employment is zero. Actuals are zero. In Manipur, it is zero, zero, zero. In Meghalaya, it is zero, zero, zero. In Sikkim, it is zero, zero, zero. In Arunachal Pradesh, it is zero, zero, zero, In Mizoram, it is zero, zero, zero. It has been stated in the reply that during the 8th Five Year Plan, Rs. 523 lakhs were for Rajasthan, Rs. 180 lakhs for some other State and Rs. 8.1 lakhs for Assam. Sir, the multinationals and foreign campanies have been developing their industries in this particular field in such a way that the whole domestic entrepreneurship will completely lose. The food processing industry in Assam and the North-East has got a great potential in this respect. Only the other day, an expert committee of the Agriculture Ministry, of which I happen to be a member, went there and we were rather stunned to know about the variety of horticultural assets in the North-Eastern region.

May I know whether the Minister will take some positive and concrete steps to

develop the food processing industry in the Nort-Eastern region, particularly in Assam?

SHRI DILIP KUMAR RAY: Sir, I have already mentioned that fortunately five IMs have been filed. Besides this, we have already spent money for expansion and modernisation of two fruit and vegetable processing units. We have given Rs. 66 lakhs. We have given Rs. 38.99 lakhs for processing of oyster mushrooms in Guwahati. There are 23 food processing training centres which have been opened and we have given Rs. 80 lakhs on that count. For setting up of sheep and goat processing plants at Khanpara, Guwahati, we have given Rs. 3.29 crores. For the food processing plant at Nazira, Guwahati, we have given Rs. 2.13 crores. For poultry processing plant at Guwahati, we have given about Rs. 2.36 crores. So far as the details of the IMs filed are concerned, we have already earmarked Rs. 171 crores for cereal based products. For fruits and vegetables, it is one crore of rupees. For fermentation industry, it is Rs. 11 crores. For edible oils and oilseeds, it is again about Rs. 11 crores. This comes to a total of Rs. 194 crores. We are giving a lot of importance to the North-East. The total assistance provided during the 8th Plan is of the order of Rs. 18.67 crores. We have already earmarked ten per cent of our expenditure to be incurred on the North-East only. For food processing plants that are coming up in the North-East, we are giving 75% as grant on that count.

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, I had quoted the answer that was given in reply to a question in July, 1996. Now I find that so many crores have been earmarked. How could these figures be there? I speak with a full sense of responsibility.

SHRI DILIP KUMAR RAY: Sir, I also speak with the full sense of responsibility. These are the IMs filed after that.

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I agree with my hon. colleague that the food processing industry has immense scope in Assam and other North-Eastern States. In this context, I would like to ask of the hon. Minister whether he has studied the impact of the recent decision of the Government to impose eight per cent Excise Duty on a large number of agro-processing industries. In 1991, all these industries were exempted from Excise Duty, but in the recent Finance Bill, eight per cent Excise Duty has been imposed. Will the hon. Minister enlighten us what will be the impact of this levy on the growth of food processing industry in India as a whole and in the North-Eastern State, in particular?

SHRI DILIP KUMAR RAY: Sir, just yesterday, we took a meeting to discuss this enhancement of Excise Duty. This Excise Duty has been levied on items which are having zero Excise Duty at present. It is going to hit the industry. We are going to take it up with the Finance Minister very soon.

SHRI SATISH AGARWAL: Thank you very much, Sir. In addition to or as a supplementary to Dr. Manmohan Singh's question, there is another question which arises out of that question and that is this; Sir, in the answer, the hon. Minister has mentioned with regard to approval of projects also. That is one of the functions of the food processing industry. There is a lot of potential available in the North-East, Rajasthan, Madhya Pradesh and other areas also and this can provide employment to the rural sector. I would like to know whether you are going to protest before a final decision is taken regarding de-reservation of items exclusively meant for the small scale sector because these food processing units are also in the small scale sector. So far as Rajasthan is concerned, I know it and same is the position in the whole country.

I have read about Abid Hussain Committee's Report in today's newspapers. The Government is going to

de-reserve items exclusively reserved for the small scale sector. Will you take up this question with the concerned Ministry, i.e. the Ministry of Industry, and also with the Cabinet and see that this de-reservation is not resorted to indiscriminately?

SHRI DILIP KUMAR RAY: Sir, two items, namely, ice cream and biscuits have been de-reserved and no other industry has been de-reserved now. No other items will be de-reserved.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Minister, Abid Hussain Committee's recommendations are there in today's newspapers. You see to it.

SHRI DILIP KUMAR RAY: Yes, Sir. These are the two items which have been de-reserved, but we wil take it up and see that no other items are de-reserved.

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदय, आज देशभर में हजारों मीट्रिक टन फल विधायिन सुविधा न होने के फलस्वरूप गत-सड़ जाता है। ऐसा फल विधायिन के लिए तो उपयुक्त है लेकिन मार्किट के लिए उपयुक्त नहीं है। वह भी मार्किट में बेचा जाता है। फलस्वरूप फल-उत्पादक को उसकी सही कीमत नहीं मिलती है और अगर फल उत्पादक खुद विधायिन करे तो मार्केटिंग की प्राब्लम आती है क्योंकि सिन्थेटिक पेय पदार्थों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो सिन्थेटिक पेय पदार्थ बनाते हैं उनको क्या आप बाध्य करेंगे कि कम से कम 20 प्रतिशत उसमें फल-रस का होना अनिवार्य किया जाये? ऐसी कम्पनियों को आप इस बात पर बाध्य करेंगे कि उनका लाइसेंस उन्हें तभी दिया जायेगा जब वे वहां पर कम से कम 20 प्रतिशत शुद्ध फल-रस तैयार करें और बेचें।

SHRI DILIP KUMAR RAY: Sir, this does not come within the purview of this question. The hon. Member has come up with a Private Member's Bill and I will answer it at that time.

Beneficiaries of Minority Communities under IRDP/TRYSEM/JRY

*362. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of beneficiaries belonging to minority communities under IRDP/TRYSEM/JRY, during the year 1995-96, State-wise;

(b) whether Government have any other schemes for minorities; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Coverage of beneficiaries belonging to minority communities is not monitored under IRDP/TRYSEM/JRY Schemes.

(b) and (c) Does not arise.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, this is the most disappointing answer which the hon. Minister has given. Sir, coverage of beneficiaries under various Central Government schemes is to be monitored to see whether various sections of the society are receiving their share and whether these benefits are being given to them.

Sir, the monorities have a feeling, and it is a correct feeling, that they are not getting the benefit from the various schemes of the Government of India as well as of the State Governments, in the dispensation of various schemes. Now, if the State Government or the Central Government is not monitoring whether these benefits are reaching the various sections of the society, how do the Ministry ensures that the benefits are reaching them? I would like to know from the hon. Minister whether he is going to set up a monitoring cell at the district as well as at the State level to monitor various schemes of the Government.

SHRI K. YERRANNAIDU: Hon. Chairman, Sir, there are monitoring cells. Even under the Twenty Point Programme